जे.वी. गुप्ता जे. के समक्ष

हर चंद, अपीलकर्ता

बनाम

रंजीत और अन्य-प्रतिवादी।

1977 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1894।

28 अप्रैल 1986

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 11 - गोद लेने के प्रभाव की दलील देने वाले पक्षों के बीच मुकदमा - मुद्दा विधिवत तैयार किया गया लेकिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष बहस के दौरान प्रासंगिक नहीं होने के कारण छोड़ दिया गया - अपीलीय न्यायालय, हालांकि, मुद्दे के संबंध में टिप्पणी कर रहा है - जैसे अवलोकन को ओबिटर की प्रकृति में माना जाता है - गोद लेने पर सवाल उठाने वाले समान पक्षों के बीच दूसरा मुकदमा - पहले मुकदमे में अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष - क्या दूसरे मुकदमे में पार्टियों के बीच पुनर्न्याय के रूप में कार्य किया जा सकता है।

माना गया कि जहां गोद लेने की दलील पहले मुकदमे में एक चरण में ली गई थी, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया था। हालाँकि, मुकदमे में विवाद का फैसला करने के लिए उक्त याचिका बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। इसके अलावा, पहले मुकदमे की अपील में गोद लेने के सवाल पर फैसला नहीं किया गया था। इसलिए, पहले मुकदमे में अपीलीय न्यायालय की टिप्पणी आज्ञाकारिता से अधिक कुछ नहीं थी और इस प्रकार पहले मुकदमे में दिया गया निर्णय दूसरे मुकदमे में पक्षों के बीच पुनर्निरीक्षण के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(पैरा 3)

बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ वरिष्ठ उप-न्यायाधीश की अदालत, जिंद, 18 नवंबर, 1977 के फैसले से नियमित दूसरी अपील, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, नरवाना, दिनांक 24 अगस्त, 1976 की डिक्री की पुष्टि वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ 28 कनाल 17 मरला की कृषि भूमि के कब्जे की लागत के साथ एक डिक्री पारित करना, जैसा कि गांव दनौदा खुर्द की राजस्व संपत्ति में स्थित वाद के शीर्षक में वर्णित है।

अपीलकर्ता की ओर से भूप सिंह, अधिवक्ता एवं सरवन गुप्ता, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से वी.के. जैन, अधिवक्ता।"

निर्णय

जे.वी. गुप्ता जे.

(1) यह प्रतिवादी की दूसरी अपील है जिसके खिलाफ कृषि भूमि पर कब्जे के मुकदमे का फैसला नीचे की दोनों अदालतों द्वारा किया जा चुका है।

(2) 'वादी रंजीत ने कृषि भूमि पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि प्रतिवादी हर चंद उसका सगा भाई था, वे दोनों भाई सुख और गोला के पुत्र थे; मुकदमा शुरू होने से लगभग 25 वर्ष पहले गोला की मृत्यु हो गई; कि हर चंद, प्रतिवादी नंबर 1, को एमएसटी द्वारा गोद लिया गया था। जिवानी गोला की मृत्यु के बाद डेटा की विधवा और वह, इस प्रकार, सुश्री का पुत्र था। जिवानी श्रीमती की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति उनके दत्तक पुत्र होने के कारण हर चंद के पक्ष में परिवर्तित कर दी गई थी, और इस प्रकार, वह श्रीमती द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मालिक थे। सुश्री द्वारा हर चंद को गोद लेने के मद्देनजर, वह अपने प्राकृतिक पिता गोला द्वारा छोड़ी गई किसी भी संपत्ति का हकदार नहीं था, और वादी गोला का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते, प्रश्न में संपत्ति का विशेष मालिक था। वाद भूमि का स्वामित्व गोला के पास था और राजस्व रिकॉर्ड में वाद भूमि के मालिक के रूप में हर चंद का उल्लेख करने वाली कोई भी प्रविष्टि अवैध, तथ्यों के विरुद्ध थी और वादी पर बाध्यकारी नहीं थी, कि हर चंद ने मुकदमे की जमीन पर प्रतिवादी नंबर 2, यानी मुंशी को कब्जा दे दिया था, और इसलिए, उसे मुकदमे में एक पक्ष बनाया गया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि पहले हर चंद ने वादी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था, और उस मुकदमे में अपील में यह माना गया था कि प्रतिवादी, हर चंद, अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं था, और, इसलिए, यह पक्षों के बीच निर्णय के रूप में कार्य करेगा। मुकदमे का विरोध इस आधार पर किया गया कि उनके पिता गोला की मृत्यु मुकदमा शुरू होने से लगभग 40 वर्ष पहले हो गई थी। प्रतिवादी हर चंद को श्रीमती ने कभी गोद नहीं लिया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, कि उसने जिवानी की भूमि पर केवल अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार, वह उसका मालिक बन गया, गोला की मृत्यु के बाद, उसकी भूमि भी हर चंद के पक्ष में बदल दी गई, और श्रीमती द्वारा उसे कथित रूप से गोद ले लिया गया। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि प्रश्न में दत्तक ग्रहण हुआ था, तो जिवानी प्रथागत कानून के तहत थी; कि उन्होंने विवादित भूमि के संबंध में कभी कोई मुकदमा दायर नहीं किया और इसलिए, पूर्व के मुकदमे की वर्तमान मुकदमे के लिए कोई प्रासंगिकता है या नहीं है; कि पहले मुकदमे में शामिल घर का आवासीय स्थल वादी द्वारा कस्टोडियन से खरीदा गया था, और वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी हर चंद, श्रीमती का दत्तक पुत्र था। जिवानी को गोला की मृत्यु के बाद गोद लिया गया था और उन्हें श्रीमती की संपत्ति विरासत में मिली थी। जिवानी का उस पर कब्ज़ा था। निचली अदालतों के समक्ष पक्षों के बीच मुख्य विवाद संख्या 7-ए के तहत था, जो 21 दिसंबर, 1975 के पहले के फैसले के मद्देनजर पुनर्न्याय के प्रश्न से संबंधित था(कॉपी पूर्व पीएल)। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया कि उक्त निर्णय पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य करता है।

और, इसलिए, मुकदमे का फैसला वादी के पक्ष में कर दिया गया। अपील में, उन्नत अपीलीय शक्तियों के साथ विद्वान वरिष्ठ उप-न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की, और इस प्रकार, मुकदमे को खारिज करने के डिक्री को बरकरार रखा। इससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी हरचंद ने यह द्वितीय अपील दायर की है।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे में दिया गया पूर्व निर्णय न्यायिक के रूप में काम नहीं करेगा क्योंकि वादी रंजीत (उस मुकदमे में प्रतिवादी) द्वारा ली गई याचिका को उस समय उसके द्वारा छोड़ दिया गया था। उस मुकदमे में तर्कों की. यह मुद्दा संख्या 4 था जिसे ट्रायल कोर्ट ने उस मुकदमे में तय किया था, जो इस प्रकार है: -

"क्या वादी द्वारा गोद लिए जाने के आधार पर विवादित भूमि पर श्रीमती जिवानी का कोई अधिकार नहीं है?"

इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय ट्रायल कोर्ट-आदेश की प्रति देखें। पीएक्स/4, दिनांक 21 दिसंबर, 1972, इस प्रकार मनाया गया –

"इस मुद्दे को प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने इसे तथ्यों से प्रासंगिक नहीं होने के कारण छोड़ दिया था।"

इस प्रकार, पहले मुकदमे में पक्षों के बीच मुख्य विवाद यह था कि क्या वादी विवाद में संपत्ति का मालिक था या नहीं। गोद लेने के संबंध में वादी द्वारा उस मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में ली गई यह याचिका पहले देखी गई तरह छोड़ दी गई थी। हालाँकि, अपील में, विद्वान जिला न्यायाधीश ने कहा:

"इस तरह, वादी को अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिल सकता है, और इस संबंध में भी, वादी के पास कोई मामला नहीं है।"

इन टिप्पणियों के आधार पर ही नीचे की अदालतों ने पाया कि यह पार्टियों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपील में विद्वान जिला न्यायाधीश की उक्त टिप्पणियाँ मान्य थीं क्योंकि अपील को उक्त टिप्पणियों के बिना निपटाया जा सकता था। इसके अलावा, विद्वान वकील ने तर्क दिया, ट्रायल कोर्ट में वादी (उस मुकदमे में प्रतिवादी होने के नाते) ने गोद लेने की याचिका छोड़ दी थी, और इसलिए, इन परिस्थितियों में पहले का फैसला पार्टियों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में काम नहीं कर सकता था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इस संबंध में निचली अदालतों का निष्कर्ष गलत और अवैध था। मुझे इस विवाद में दम नजर आता है, कोई सार्थक तर्क नहीं हो सका

नीचे की अदालतों के इस निष्कर्ष के समर्थन में वादी-प्रतिवादियों की ओर से उठाया गया। विद्वान वकील के अनुसार, भले ही पक्षों के बीच कोई गलत निर्णय हुआ हो, यह उन पर बाध्यकारी था और यह न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने इस संबंध में मोहनलाल गोयनका बनाम बेनॉय किशना मुखर्जी (1) और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हेमंत कुमार भट्टाचार्जी (2) का हवाला दिया। उक्त प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। हालाँकि, वर्तमान मामले में, गोद लेने की दलील हालांकि वादी (उस मुकदमे में प्रतिवादी) द्वारा एक चरण में ली गई थी, लेकिन बाद में छोड़ दी गई थी। इसके अलावा, उक्त याचिका उस मुकदमे में विवाद का फैसला करने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। उस मुकदमे में प्रतिवादी ने वादी के रूप में दावा किया कि मुकदमा संपत्ति उसकी विशेष संपत्ति है जिसे उसने कस्टोडियन से खरीदा है। इस प्रकार, सुश्री द्वारा उनके गोद लेने का प्रश्न बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थी। इन्हीं परिस्थितियों में

बाद में याचिका छोड़ दी गई। इसके अलावा, अपील में भी, मामला केवल गोद लेने के सवाल पर तय नहीं किया गया था। यह केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई एक टिप्पणी थी जो कि आज्ञाकारिता से अधिक कुछ नहीं थी। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, पहले का निर्णय पक्षों के बीच पूर्व निर्णय के रूप में कार्य नहीं करता था। इस संबंध में निचली अदालतों का पूरा दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत, अवैध और गलत धारणा वाला था।

(4) यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी हरचंद को आश्रित पिता गोला की मौत के बाद, सुश्री द्वारा गोद लिया गया था। माना जाता है कि, प्रतिवादी हर चंद, अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी था। एक बार जब वह अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में सफल हो गया तो उसे बाद में उससे वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसे सुश्री द्वारा गोद लिया गया था। जिवानी, हिंदू कानून के तहत भी और प्रथा के तहत भी। इस संबंध में मधद साहू बनाम हटकिशोर साहू (3) ए.आई.आर. का संदर्भ लिया। 1975 उड़ीसा, जहां यह माना गया था कि "जिस परिवार में वह पैदा हुआ है, उस परिवार से गोद लिए गए बच्चे को पूरी तरह से अलग करने का सिद्धांत उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां गोद लेने से पहले ही पूर्ण मालिक के रूप में संपत्तियां व्यक्तिगत रूप से निहित हो चुकी हैं, या तो अपने प्राकृतिक परिवार में एकमात्र जीवित सह-पारिसर या विरासत से या विभाजन से। जहां तक सीमा शुल्क के तहत स्थिति का संबंध है, इस स्थिति को सोहन सिंह बनाम गुरतेज सिंह (4) में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दोहराया गया था, इस टिप्पणी के साथ कि "के तहत गोद लेने के बीच एकमात्र अंतर है"

(1)A.I.R. 1953 S.C. 65.
(2)A.I.R. 1966 S.C. 1061.
(3)A.I.R. 1975 Orissa 48.
(4)1971 CJL 942.

प्रथागत कानून और हिंदू कानून के तहत दत्तक ग्रहण यह है कि यदि बेटे को प्रथागत कानून के तहत नियुक्त किया जाता है तो वह परिवार के साथ सभी संबंध नहीं खोता है। वह अपने प्राकृतिक परिवार में संपार्श्विक उत्तराधिकार का अधिकार बरकरार रखता है, जबकि हिंदू कानून के तहत गोद लेने के मामले में उसका प्राकृतिक परिवार से कोई संबंध नहीं रह जाता है।" इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बार अपीलकर्ता-प्रतिवादी अपने प्राकृतिक पिता के उत्तराधिकारी बन गया तो उसे इस आधार पर उससे वंचित नहीं किया जा सकता था कि बाद में उसे एमएसटी द्वारा गोद लिया गया था।

(5) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है, निचली अदालतों के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है, और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

R. N. R.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा